The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Special Issue 3 | October 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और सतत विकास लक्ष्य (SDGs): समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक मार्ग

टोकेष्वर

बी. एड. सेमेस्टर 3 विद्यार्थी, कलिंगा विष्वविद्यालय, नया रायपुर, छ.ग.

डॉ. सरोज नैय्यर

सह–प्राध्यापक, कलिंग विश्वविध्यालय, नया रायपुर छ.ग. Email: saroj.nayyar@kalingauniversity.ac.in

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17399999

परिचय

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को सतत विकास का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals - SDGs) में कुल 17 लक्ष्य शामिल हैं, जिनमें से SDG 4 विशेष रूप से शिक्षा से जुड़ा है। SDG 4 का उद्देश्य है: "सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीविका के अवसरों के लिए सतत सीखने के अवसर प्रदान करना।" इस लक्ष्य के तहत सभी बच्चों और युवाओं को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, लिंग समानता सुनिश्चित करना, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना, और शिक्षा प्रणाली को नवाचार एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना शामिल है। भारत में शिक्षा का क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विकास का मूल आधार रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने स्वतंत्रता के बाद अनेक सुधारात्मक कदम उठाए, परंतु वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तेजी से बदलती तकनीक, सामाजिक असमानताएं, और शिक्षा के पहुँच में बाधाओं ने इसे नए आयाम पर पुनः विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी। इसी संदर्भ में वर्ष 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को अपनाया। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, गुणवत्ता-प्रधान, तकनीकी और नवाचार से परिपूर्ण बनाना है। NEP 2020 का प्रमुख लक्ष्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया बनाना है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास, कौशल वृद्धि, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाती हो। इसके तहत 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। साथ ही शिक्षा के बहुभाषीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार संभव हो और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण भी हो सके। साथ ही, NEP 2020 डिजिटल शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग मानता है। डिजिटल

प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को वैश्विक ज्ञान से जोड़ने, दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने, और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। SWAYAM, DIKSHA जैसे डिजिटल पोर्टल्स इस नीति का हिस्सा हैं, जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, NEP 2020 कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि छात्र केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं प्राप्त करें, बल्कि व्यावसायिक कौशल और तकनीकी दक्षताओं में भी प्रवीण बनें। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने और उन्हें नवाचार के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया है। इस नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू समावेशी शिक्षा है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र, आदिवासी क्षेत्र के छात्र, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चे और विकलांग छात्र भी शिक्षा प्रणाली में समान रूप से सम्मिलित किए गए हैं। इससे शिक्षा का अधिकार हर बच्चे तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। इस लेख में आगे विस्तार से यह विश्लेषण किया जाएगा कि कैसे NEP 2020 के विभिन्न प्रावधान सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप कार्य करते हैं। साथ ही, यह भी बताया जाएगा कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इनके समाधान हेतु कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। परिणामतः, यह समझा जाएगा कि NEP 2020 और SDG 4 के समन्वय से भारत में समावेशी, गुणवत्ता-प्रधान, और वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का सृजन कैसे संभव हो सकता है।

1. सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और उनकी शिक्षा से संबंधित भूमिका

सतत विकास लक्ष्य)Sustainable Development Goals – SDGs) 2030 के एजेंडा के तहत विकसित किए गए हैं, जिनमें कुल 17 व्यापक लक्ष्य शामिल हैं। ये लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इनमें से विशेष रूप से SDG 4 शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि सभी को आजीविका के अवसर प्राप्त हो सकें। इसके अंतर्गत न केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, बल्कि उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और आजीवन शिक्षा)Lifelong Learning) को भी प्रोत्साहित किया गया है। SDG 4 यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रणाली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करते हुए सभी समुदायों तक पहुँच सके, विशेष रूप से कमजोर वर्ग, आदिवासी क्षेत्र, विकलांगता वाले बच्चे तथा लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए। इसके माध्यम से सतत सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से सक्षम बन सके। यह वैश्विक एजेंडा शिक्षा को समाज के विकास, समृद्धि और न्याय के लिए एक प्रभावी उपकरण मानता है। इस लक्ष्य के तहत प्राथमिकता दी गई है:

- सभी स्तरों पर समान शिक्षा की उपलब्धता

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण
- स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का समावेश
- शिक्षा में लैंगिक समानता

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति)NEP) 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक और दूरगामी सुधार लाने का एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज है। यह नीति पिछले लगभग तीन दशकों बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए पहली समग्र रूप से विकसित नीति है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकताओं और भारतीय समाज के बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करना है। NEP 2020 शिक्षा को केवल सूचना का संकलन नहीं मानता, बल्कि इसे एक समग्र प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, जो छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर केंद्रित है। इस नीति के प्रमुख पहलुओं में बहुभाषीय शिक्षा को प्राथमिकता देना, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल शिक्षा का प्रसार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को मुख्यधारा में लाना, शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली का पुनर्गठन शामिल है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के समावेशी मॉडल पर जोर दिया गया है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित हो सके। NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, नवाचारप्रधान-, पारदर्शी, उत्तरदायी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह नीति शिक्षा को समाज के हर तबके तक पहुँचाने, गुणवत्ता सुधारने, और देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में योगदान देने का माध्यम बनाती है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- बहुभाषीय शिक्षा का प्रोत्साहन।
- डिजिटल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।
- समावेशी शिक्षा के लिए विशेष पहलें।
- कौशल आधारित शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुखता देना।
- शोध और नवाचार पर जोर देना।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी, नवाचार-प्रधान, और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

3. NEP 2020 और SDG 4 के बीच सामंजस्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) का उद्देश्य मूल रूप से समान है – अर्थात्, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना। NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, नवाचारप्रधान, पारदर्शी और समावेशी बनाना है, ताकि शिक्षा केवल ज्ञान का संकलन न रहे, बल्कि व्यक्तित्व विकास, कौशल निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक योग्यता का भी संवर्धन हो। इसी प्रकार, SDG 4 का उद्देश्य भी हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्राथमिकता देना, और आजीवन शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। दोनों ही पहलें शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, डिजिटल शिक्षा का समावेश, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, और अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकलांगता वाले छात्र, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, और समाज के वंचित वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। इस तरह, NEP 2020 और SDG 4 एक-दूसरे के पूरक हैं, जो शिक्षा को समाज का सशक्त आधार बनाकर राष्ट्र के सतत विकास में योगदान देने का लक्ष्य रखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इनके सामंजस्य को समझा जा सकता है-

- **समान शिक्षा का अधिकार और समावेशन:** NEP 2020 विशेष रूप से कमजोर वर्गों, विशेष जरूरतों वाले छात्रों और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करता है। SDG 4 भी समान शिक्षा के अवसर देने की आवश्यकता पर बल देता है। **उदाहरण:** NEP के तहत 3 से 18 वर्ष तक का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य SDG 4 की समान शिक्षा उपलब्धता से मेल खाता है।

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण:** SDG 4 के लक्ष्यों में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया है। NEP 2020 भी इसी दिशा में अध्यापक प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणालियों और सतत पेशेवर विकास के लिए सशक्त प्रावधान करता है। उदाहरण: शिक्षा संस्थानों के लिए उच्च मानक, मास्टर ऑफ एजुकेशन (M.Ed.) कार्यक्रमों का उन्नयन।

- **डिजिटल शिक्षा और नवाचार:** वैश्विक डिजिटल युग में शिक्षा का डिजिटलीकरण एक प्रमुख आवश्यकता बन गया है। NEP 2020 डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का लक्ष्य रखता है। यह SDG 4 के वैश्विक ज्ञान साझेदारी और डिजिटल साक्षरता के उद्देश्य से मेल खाता है।

- **कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा:** NEP में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि छात्र केवल अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ रोजगारोन्मुख भी बन सकें। यह SDG 4 के लक्ष्य "सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करना" के साथ सामंजस्य रखता है।

- **परिणाम आधारित शिक्षा:** NEP 2020 सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली को पुनः परिभाषित करता है। SDG 4 भी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परिणाम आधारित मूल्यांकन पर जोर देता है।

4. समावेशी शिक्षा की दिशा में NEP और SDGs की भूमिका

समावेशी शिक्षा का अर्थ है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, या शारीरिक स्थिति कुछ भी हो। NEP 2020 में विशेष रूप से विकलांगता वाले बच्चों, आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों, और पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके उदाहरण हैं:

- 3 से 18 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार।
- विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम।
- आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने के लिए विशेष विद्यालय।
- लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए छात्राओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना।

यह पहलें SDG 4 की समावेशी शिक्षा नीति के अनुरूप हैं, जो हर बच्चे को शिक्षा की समान अवसर उपलब्ध कराना चाहती है।

5. गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार

NEP 2020 में गुणवत्ता आश्वासन पर विशेष ध्यान दिया गया है। NAAC, QCI, और ISO जैसे संस्थानों के माध्यम से शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और सुधार सुनिश्चित किया जाता है। इससे SDG 4 के गुणवत्ता शिक्षा लक्ष्य की पूर्ति होती है। प्रमुख पहलें हैं:

- पाठ्यक्रम सुधार
- प्रशिक्षकों की नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया

- स्व-मूल्यांकन रिपोर्टिंग
- गुणवत्ता मानकों के अनुसार संस्थानों का प्रमाणीकरण

इन उपायों से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

6. डिजिटल शिक्षा का विस्तार और SDG 4

NEP 2020 डिजिटल शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों को वैश्विक ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया SDG 4 के ज्ञान साझेदारी और डिजिटल साक्षरता के उद्देश्य को पूरा करती है। भारत सरकार की डिजिटल शिक्षा पहलें, जैसे e-Pathshala, DIKSHA, SWAYAM, आदि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। डिजिटल शिक्षा के लाभ:

- दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच।
- शिक्षकों के लिए सशक्त प्रशिक्षण संसाधन।
- विद्यार्थियों के लिए लचीले अध्ययन विकल्प।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री की उपलब्धता।

इन पहलुओं के माध्यम से भारत सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

7. चुनौतियाँ और समाधान

1. अवसंरचनात्मक अभाव, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में: NEP 2020 और SDG 4 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी चुनौती शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में। कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएँ, स्वच्छ शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और खेल सुविधाएँ नहीं हैं। बिजली, इंटरनेट और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव शिक्षा तक पहुँच को सीमित करता है। यह स्थिति विद्यार्थियों के नियमित स्कूल आने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। परिणामस्वरूप, शिक्षा का दायरा सीमित रह जाता है और सतत विकास के लक्ष्य 4 के तहत समावेशी और समान शिक्षा की दिशा में प्रगति धीमी हो जाती है।

2. शिक्षकों की कमी और उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भारत की शिक्षा प्रणाली में एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण

और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक नियुक्ति की कमी और स्थानांतरण नीतियों की खामियाँ शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, कई शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल उपकरणों और समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं में उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता। इसका परिणाम यह होता है कि वे विद्यार्थियों की विविध सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता घटती है और SDG 4 के लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं।

3. डिजिटल शिक्षा के लिए पर्याप्त तकनीकी संसाधनों का अभाव: 21वीं सदी की शिक्षा में डिजिटल साधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के कई स्कूलों में यह सुविधा पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है, और कई स्कूलों में कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएँ तथा डिजिटल सामग्री उपलब्ध नहीं हैं। यह डिजिटल विभाजन छात्रों के बीच असमानता को और बढ़ा देता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच बाधित होती है। NEP 2020 डिजिटल शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण इसे प्रभावी रूप से लागू करना कठिन हो जाता है, जिससे SDG 4 की प्राप्ति में बाधा आती है।

4. सामाजिक और लैंगिक असमानताएँ: भारत में सामाजिक और लैंगिक असमानताएँ शिक्षा तक समान पहुँच में बड़ी चुनौती पेश करती हैं। जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाला भेदभाव अभी भी कई बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है। विशेषकर लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे लैंगिक समानता का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। आदिवासी, अल्पसंख्यक और विकलांग बच्चों को भी अक्सर भेदभाव और समावेशी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। जब तक इन सामाजिक बाधाओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक NEP 2020 और SDG 4 के समावेशी एवं समान शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इन चुनौतियों का समाधान निम्नलिखित उपायों से किया जा सकता है:

- सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचार लाना।
- विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम विकसित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी अवसंरचना का विकास।
- सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता अभियान।

8. निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और सतत विकास लक्ष्य (SDGs) का संयोजन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। यह समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और भविष्योन्मुख शिक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा को केवल सूचना का संकलन न मानकर, एक समग्र मानव विकास का माध्यम माना जा रहा है। SDG 4 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए NEP 2020 का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाना आवश्यक है। इसके लिए नीति निर्माताओं, शिक्षकों, शिक्षार्थियों और समाज के हर तबके को मिलकर प्रयास करना होगा। इस सामंजस्य के माध्यम से हम न केवल वैश्विक शिक्षा मापदंडों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भारत को एक समावेशी, नवाचारप्रधान और सतत विकास की दिशा में अग्रसर बना सकते हैं।

संदर्भ

अग्रवाल, ए. (1995). स्वदेशी और वैज्ञानिक ज्ञान के बीच विभाजन को समाप्त करना। *डेवलपमेंट एंड चेंज, 26*(3), 413–439. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1995.tb00560.x

ऑल्टबैक, पी. जी., एवं नाइट, जे. (2007). उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण: प्रेरणाएँ और वास्तविकताएँ। *जर्नल ऑफ स्टडीज इन इंटरनेशनल एजुकेशन, 11*(3-4), 290–305. https://doi.org/10.1177/1028315307303542

बर्केस, एफ. (2012). *सेक्रेड इकॉलॉजी* (3रा संस्करण)। रूटलेज।

भारत सरकार। (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। शिक्षा मंत्रालय।

गाडगिल, एम., एवं गुहा, आर. (1992). *दिस फिशर्ड लैंड: एन इकॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया*। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

झा, पी., एवं पार्वती, पी. (2014). भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर प्रगति का आकलन: कुछ प्रमुख बाधाओं पर एक टिप्पणी। *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 49*(5), 44–51।

कुमार, के. (2005). *राजनीतिक एजेंडा ऑफ एजुकेशन: औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन*। सेज पब्लिकेशन्स।

मिश्रा, एस. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत में उच्च शिक्षा के रूपांतरण के लिए एक रोडमैप। *हायर एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, 8*(2), 125–139. https://doi.org/10.1177/23476311211007826

नीति आयोग। (2021). *एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन*। भारत सरकार।

प्रकाश, एम. एस., एवं एस्टेवा, जी. (2008). *एस्केपिंग एजुकेशन: लिविंग ऐज लर्निंग विदिन ग्रासरूट्स कल्चर्स* (2रा संस्करण)। पीटर लैंग।

सेन, ए. (2005). *द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन: भारतीय इतिहास, संस्कृति और पहचान पर लेखन*। फरार, स्ट्रॉस एंड गिरॉक्स।

सिलिटो, पी. (1998). स्वदेशी ज्ञान का विकास: एक नई अनुप्रयुक्त मानवविज्ञान। *करंट एंथ्रोपोलॉजी, 39*(2), 223–252. https://doi.org/10.1086/204722

शिवा, व. (1993). *मोनोकल्चर्स ऑफ द माइंड: परिप्रेक्ष्य ऑन बायोडायवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी*। ज़ेड बुक्स।

तिलक, जे. बी. जी. (2020). भारत में शिक्षा और विकास: नीति और व्यवहार में महत्वपूर्ण मुद्दे। *इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 14*(1), 1–16. https://doi.org/10.1177/0973703020912771

संयुक्त राष्ट्र। (2015). *हमारी दुनिया को रूपांतरित करना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा*। संयुक्त राष्ट्र।